



- प्रधानमंत्री के ग्यारह वर्षों के शासन पर भाजपा ने किया प्रदर्शनी का आयोजन।
- प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ने उपलब्ध कराए दस करोड़ से अधिक एल पी जी कनेक्शन।
- परिवहन विभाग द्वारा द्वीपसमूह में चलाया जाएगा परिवहन विभाग आपके द्वार कार्यक्रम।
- राधानगर बीच पर हुआ योगाभ्यास कार्यक्रम।



अंडमान निकोबार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अजय बैरागी ने कल शाम मिडिल प्वाइंट स्थित भाजपा मुख्यालय में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में परिवर्तन कार्य शासन के शानदार ग्यारह वर्षों की प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। इस प्रदर्शनी में सभी प्रमुख विकास और प्रशासनिक कार्यों को प्रदर्शित किया गया है, जिससे समाज के जरूरतमंद और उपेक्षित वर्गों को योजनाओं का लाभ मिल सके। यह प्रदर्शनी आज भी खुली रहेगी। इस समाचार की जानकारी प्रदेश उपाध्यक्ष एम विनोद ने दी।



केन्द्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत पूरे देश में अब तक दस करोड़ तैंतीस लाख मुफ्त एल पी जी कनेक्शन उपलब्ध कराए गए हैं। वे कल सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों और पेट्रोलियम मंत्रालय के अधिकारियों की एक बैठक को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि देश ऊर्जा के हरित, टिकाऊ और प्रगतिशील स्रोतों पर ध्यान केन्द्रित करते हुए ऊर्जा सुरक्षा लक्ष्यों की तरफ आगे बढ़ रहा है।



ईरान की राजधानी तेहरान में भारतीय दूतावास ने सुरक्षा कारणों से भारतीय विद्यार्थियों को शहर से बाहर भेज दिया है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि जिन नागरिकों के पास आने जाने की अपनी व्यवस्था है, उन्हें भी स्थिति को देखते हुए शहर से बाहर जाने को कहा गया है। कुछ भारतीयों को आर्मेनिया से लगने वाली सीमा से ईरान से बाहर निकलने की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। दूतावास लगातार भारतीय समुदाय के सम्पर्क में है।



जम्मू-कश्मीर सरकार ने अमरनाथ गुफा तीर्थस्थल तक जाने वाले सभी रास्तों को यात्रा के दौरान उड़ान वर्जित क्षेत्र घोषित कर दिया है। जम्मू-कश्मीर के उप-राज्यपाल मनोज सिन्हा के आदेशानुसार अगले महीने की पहली तारीख से दस अगस्त तक पहलगाम और उसके आसपास तथा बालतल सहित अमरनाथ यात्रा के सभी रास्तों पर यूएवी, ड्रोन और गुब्बारों सहित सभी प्रकार की उड़ानों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। परन्तु, चिकित्सा संबंधी मामलों, आपदा प्रबंधन और सुरक्षा बलों

की निगरानी पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। इस बीच, आगामी अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा तैयारियों के लिए केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने उच्च स्तरीय बैठक की, जिसमें अमरनाथ यात्रा की तैयारियों और सुरक्षा संबंधी योजना को अंतिम रूप दिया गया। वरिष्ठ अधिकारियों ने संभावित खतरों और चुनौतियों से निपटने के लिए सुरक्षा उपायों के क्रियान्वयन और योजना तैयार की जरूरत पर बल दिया।

अधिकारियों ने कहा है कि इसके लिए समस्त एजेंसियों के बीच समन्वय बनाये रखने के उपायों को सुनिश्चित किये जाने की आवश्यकता पर बल दिया गया है। हिमालय पर्वत स्थित तीन हजार आठ सौ अट्ठासी मीटर ऊंचाई स्थित तीर्थस्थल की वार्षिक यात्रा तीन जुलाई से शुरू होगी और नौ अगस्त को रक्षा बंधन के अवसर पर सम्पन्न होगी।



परिवहन विभाग आपके द्वार कार्यक्रम के अंतर्गत एकीकृत सड़क सुरक्षा एवं परिवहन सेवा आउटरीच कार्यक्रम का आयोजन करेगा, जिसका उद्देश्य शहीद द्वीप, लिटिल अंडमान और संपूर्ण मध्योत्तर अंडमान के साथ-साथ निकोबार जिले में ग्रामीण पंचायतों और गांव में सड़क सुरक्षा जागरूकता को मजबूत करना है। इसके साथ ही परिवहन सेवाओं में सुधार करना भी विभाग का लक्ष्य है। इस पहल के माध्यम से ग्रामीणों को यातायात नियमों, सड़क उपयोग की जिम्मेदारियों और सुरक्षित ड्राइविंग के प्रति जागरूक करना है। इन शिविरों के दौरान चिकित्सा परीक्षण, लर्नर्स लाइसेंस परीक्षण, ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण, सड़क कर का संग्रहण और वाहन फिटनेस प्रमाणपत्र जैसी सेवाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी जाएगी।



केन्द्रीय द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्थान की ओर से कार निकोबार के कृषि विज्ञान केन्द्र के सहयोग से ननकौड़ी द्वीपसमूह के अनुसूचित जनजाति के लिए बारह से चौदह जून तक कंद फसलों पर आधारित “एकीकृत कृषि प्रणाली के तहत प्राकृतिक खेती के तरीके” शीर्षक से एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रधान वैज्ञानिक डॉ. जय शंकर ने एकीकृत कृषि प्रणाली के लाभ और संभावनाओं के बारे में कृषि आय बढ़ाने के विभिन्न तरीके बताए। ननकौड़ी द्वीपसमूह के ककाना, पिलपिलो और मुनाका गांव के कुल एक सौ उनतालीस किसानों ने प्रशिक्षण में भाग लिया। इसके साथ ही महिला किसानों को कृषि संबंधी पचास इकाईयां वितरित की गई। कार्यक्रम का आयोजन डॉ. ई बी चाकुरकर के मार्गदर्शन में किया गया।



ग्यारहवें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्वराज द्वीप की आयुष इकाई ने राधानगर बीच पर इवनिंग सनसेट बीच योगा सेशन का आयोजन किया। इस वर्ष की योग दिवस की थीम एक पृथ्वी—एक स्वास्थ्य के लिए योग के माध्यम से स्वास्थ्य और कल्याण के संदेश को बढ़ावा देने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। योग प्रशिक्षक वेंकटेश्वरी के नेतृत्व में प्रणायाम सहित अन्य योग क्रियाएं सम्पन्न की गईं। योग कार्यक्रम को सभी आयु समूह के अनुरूप बनाया गया था, जिससे सभी को उसका लाभ मिल सके।



मॉक ड्रिल आयोजित करने के क्रम में आपदा प्रबंधन निदेशालय और अंडमान निकोबार प्रशासन ने राजधानी श्री विजयपुरम स्थित पशुपालन और पशु चिकित्सा सेवा निदेशालय में भूकंप और आग की भयावह स्थिति को ध्यान में रखते हुए मॉक ड्रिल का आयोजन किया। यह अभ्यास अग्निशमन और आपातकालीन सेवाओं, परिवहन और ज़िला प्रशासन के सहयोग से आयोजित किया गया था।



सचिवालय में अमलागेटेड क्लारिकल कैडर ग्रुप बी के लिए कार्यालय अधीक्षक एवं प्रधान लिपिक, सहायक प्रभारी, सहायक के मंत्रीय स्तरीय पदों पर भर्ती के लिए मसौदा भर्ती नियम वेबसाइट पर प्रकाशित किए गए हैं। प्रकाशन के तीस दिनों के भीतर हितधारकों से दावे और आपत्तियां आमंत्रित की गई है। दावे और आपत्तियां उप-सचिव (पर्स) सचिवालय को प्रस्तुत की जा सकती है।



भगवान बिरसा मुंडा की एक सौ पचासवीं जयंती के उपलक्ष्य में वनवासी कल्याण आश्रम, मायाबंदर में विभिन्न कार्यक्रम की श्रृंखला के आयोजन के क्रम में पिछले दिनों दानापुर सामुदायिक भवन में ग्राम पंचायत पोकाडेरा के अंतर्गत कक्षा दसवीं से ऊपर के विद्यार्थियों और युवाओं के लिए **निर्माण** नामक एक दिवसीय करियर मार्गदर्शन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के माध्यम से युवाओं को दिशा और प्रेरणा दी गई। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट तरुण कुमार मंडल ने किया। श्री मंडल ने अपने संबोधन में छात्रों को अनुशासन और कड़ी मेहनत करते हुए उच्च लक्ष्य बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित किया।



मंगलुटान गांव में बीस हेक्टेयर सरकारी भूमि दक्षिण अंडमान ज़िला प्रशासन द्वारा बहाल कर दी गई है। सरकारी सम्पत्तियों की सुरक्षा और भूमि प्रशासन में कानून के शासन को बनाए रखने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए दक्षिण अंडमान ज़िला प्रशासन ने फरारगंज तहसील के अंतर्गत मंगलुटान गांव में बीस हेक्टेयर सरकारी भूमि को पुनः बहाल कर लिया है। यह भूमि जो पहले अंडमान सी-फुड कॉर्पोरेटिव सोसाइटी लिमिटेड को आवंटित की गई थी, एक दशक से लंबी चली प्रक्रियाओं के बाद भूमि बहाली के आदेश प्रशासन द्वारा कर दिए गए हैं।

